समाचार विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2003-04

वित्त मंत्री डॉ. रामचंद्र सिंह देव द्वारा छत्तीसगढ़ का तीसरा वार्षिक बजट 24-02-03 को प्रस्तुत किया गया । बजट के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं ।

बजट एक नजर में –

1. राजस्व प्राप्तियाँ

- कुल राजस्व प्राप्तियों में 26 प्रतिशत वृद्धि, 2002-03 में रूपये 5820 करोड़ से बढ़कर 2003-04 में रूपये 7328 करोड़

- राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 16 प्रतिशत वृद्धि, 2002-03 में रूपये 2289 करोड़ से बढ़कर रूपये 2003-04 में रूपये 2653 करोड़ । यह वृद्धि मुख्यत: वाणिज्यिक कर, आबकारी, परिवहन तथा पंजीयन विभाग में अधिक प्राप्तियों के कारण है ।

- राज्य का कर भिन्न राजस्व में 25 प्रतिशत वृद्धि, 2002-03 में रूपये 892 करोड़ से बढ़कर 2003-04 में रूपये 1115 करोड़ । यह वृद्धि मुख्यत: खनिज तथा जल संसाधन विभागों में अधिक प्राप्तियों के कारण है ।

- केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि संभावित, 2002-03 में रूपये 1472 करोड़ से बढ़कर 2003-04 में रूपये 1656 करोड़ । परन्तु केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 28.02.03 को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत होने के पश्चात् ही स्पष्टत: ज्ञात होगा ।

- केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान 2002-03 में 1167 करोड़ से बढ़कर 2003-04 में रूपये 1904 करोड़ । परन्तु यह वृद्धि धान के विकेन्द्रीकृत उपार्जन हेतु संभावित प्राप्ति रूपये 500 करोड़ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि की प्राप्तियाँ और व्यय राज्य के बजट के माध्यम से किये जाने के केन्द्र सरकार के निर्णय के कारण है । यदि इन राशियों के अलावा केन्द्र से प्राप्तियों को देखा जाए, तो उसमें वृद्धि काफी कम है । पूर्व में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि सीधे कियान्वयन एजेन्सियों को प्राप्त होती थी । बजट के माध्यम से व्यय से इन योजनाओं पर बेहतर नियंत्रण तथा उनकी बेहतर समीक्षा की जा सकेगी ।

2. **आयोजना व्यय**

- विकास कार्यों पर होने वाला व्यय आयोजना व्यय की श्रेणी में आता है । राज्य शासन का लगातार यह प्रयास रहा है कि आयोजना व्यय में वृद्धि हो ।

- आयोजना में व्यय में 56 प्रतिशत वृद्धि, 2002-03 में रूपये 2792 करोड़ से बढ़कर 2003-04 में रूपये 4347 करोड़ ।

- कुल व्यय में आयोजना व्यय का भाग 2002-03 में 38 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 47 प्रतिशत । अधिकांश राज्यों में यह 20-30 प्रतिशत के बीच है । इससे विकास के प्रति शासन की प्रतिबद्धता स्पष्ट है, साथ ही स्थापना, ऋण सेवा आदि पर होने वाले निश्चित व्यय का कम होना भी स्पष्ट है ।

- **विशेष क्षेत्र**
  - अधोसंरचना निर्माण पर विशेष ध्यान
  - सड़कों तथा सिंचाई परियोजनाओं को उच्चतम प्राथमिकता । 734 सड़कों, 259 पुलों, 439 सिंचाई परियोजनाओं तथा 99 एनीकट हेतु प्रावधान। 380 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रावधान ।
  - पांच नवीन पेयजल परियोजनाएँ

- राज्य आयोजना, अर्थात् राज्य की स्वयं की विकास योजनाएँ, जिनपर राज्य स्वयं के संसाधनों से व्यय करता है, में 39 प्रतिशत की वृद्धि, 2002-03 में रूपये 2043 करोड़ से बढ़कर 2003-04 में रूपये 2847 करोड़ । स्पष्ट है कि राज्य के संसाधनों से व्यय में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है ।

- राज्य द्वारा योजना आयोग को 2003-04 की प्रारूप आयोजना प्रस्तुत की जा चुकी है परन्तु उसे अभी योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है । राज्य आयोजना में वृद्धि के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं ।

3. **<u>आयोजनेत्तर व्यय</u>**

- आयोजनेत्तर व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखा गया है । वर्ष 2002-03 में रूपये 4573 करोड़ से बढ़कर 2003-04 में रूपये 4922 करोड़, मात्र 7 प्रतिशत की वृद्धि ।

- वेतन-भत्तों पर व्यय कुल व्यय के 30 प्रतिशत से कम ।

- ब्याज भुगतान 2002-03 में कुल व्यय का 12 प्रतिशत था, जो 2003-04 में घटकर 10.8 प्रतिशत होगा । ब्याज भुगतान पर कुल व्यय 2002-03 में रूपये 899 करोड़, 2003-04 में रूपये 998 करोड़ ।

4. <u>क्षेत्रवार आबंटन</u>

- 2002-03 की तुलना में बजट में 26 प्रतिशत वृद्धि, 2002-03 में रूपये 7365 करोड़ से बढ़कर 2003-04 में रूपये 9270 करोड़ ।यह वृद्धि लगभग पूर्णत: अधिक आयोजना व्यय के कारण है ।

- **<u>सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें</u>**

विभाग	2002-03	2003-04	प्रतिशत वृद्धि
स्वास्थ्य	228	244	7
अ.जा./ज.जा.कल्याण	588	734	25
महिला बाल विकास	145	177	22
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	200	218	9
स्कूल शिक्षा	652	822	26
उच्च/तकनीकी शिक्षा	91	120	32
लोक निर्माण	535	757	41
जल संसाधन	462	540	17
कृषि	156	251	61
ग्रामीण विकास	608	912	50
खाद्य / नागरिक आपूर्ति	492	751	53
ऊर्जा	145	189	30
नगरीय विकास	223	298	34
आवास पर्यावरण	63	111	76
पर्यटन	7	16	129

- बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष पैकेज ।

5. <u>घाटे के संकेतक</u>

- 2002-03 के दौरान बजटीय घाटा बजट अनुमान रूपये 550 करोड़ से घटकर पुनरीक्षित अनुमान में रूपये 199 करोड़ होना अनुमानित । यह कमी व्यय पर नियंत्रण तथा वित्तीय प्रबंधन के कारण है । 2003-04 में बजटीय घाटा रूपये 312 करोड़ होना अनुमानित ।

- 2002-03 में राजस्व घाटा रूपये 342 करोड़ होना अनुमानित, यह कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.6 प्रतिशत होगा । यह 2002-03 के राजस्व घाटे रूपये 505 करोड़ से काफी कम है, जो राजस्व प्राप्तियों का 8.6 प्रतिशत था । राजस्व घाटे में कमी कर तथा करेत्तर राजस्व में वृद्धि के कारण है । राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि बेहतर कर प्रशासन तथा प्रवर्तन के कारण है। 2003-04 में कोई नया कर आरोपित नहीं किया जा रहा है । राज्य द्वारा 2004-04 तक राजस्व घाटा शून्य करने का निर्णय लिया गया है ।

- सकल राजकोषीय घाटा 2002-03 में रूपये 1527 करोड़ से बढ़कर 2003-04 में 1923 करोड़ होगा । यह राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.4 प्रतिशत है । सकल राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का हिस्सा 2002-03 में 33 प्रतिशत से घटकर 2003-04 में मात्र 18 प्रतिशत रह जायेगा । यह अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है और इससे पूँजीगत व्यय के लिये किये गये अधिक प्रावधान की स्थिति स्पष्ट होती है ।

6. कराधान प्रस्ताव

बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है । कर ढाँचे के युक्तियुक्तकरण तथा बेहतर कर प्रशासन के माध्यम से कर राजस्व में वृद्धि की रणनीति के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, और 2003-04 में भी युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव बजट में सम्मिलित किये गये हैं । इसकी जानकारी परिशिष्ट-एक में दी गई है ।

रूपये करोड़

	2002–03	2003–04
कुल व्यय	7365.44	9269.50
कुल प्राप्तियाँ	7277.30	9156.65
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	5820.17	7327.71
कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ	1457.13	1828.94
आयोजना व्यय	2792.18	4346.95
आयोजनेत्तर व्यय	4573.26	4922.55
राजस्व व्यय	6325.49	7669.69
पूँजीगत व्यय	951.38	1487.01
बजटीय घाटा	–199.69	–312.54
राजस्व घाटा	–505.32	–341.98
सकल राजकोषीय घाटा	–1526.92	–1922.94